भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3061**
दिनांक 11 जुलाई , 2019 / 20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया के निजीकरण की स्थिति

3061. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री राहुल रमेश शेवले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया का निजीकरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) सरकार को एयर इंडिया यूनियन सहित विभिन्न पक्षों से एयर इंडिया का निजीकरण नहीं करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एयर इंडिया के ऋण में हुई कमी/वृद्धि की मात्रा और अर्जित लाभ/हुई हानि का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा एयर इंडिया में निवेश की गई पूंजी का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा एयर इंडिया को पुनर्जीविता करने और इसके निजीकरण के मामले में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): सरकार एअर इंडिया के नीतिगत विनिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28.06.2017 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के नीतिगत विनिवेश पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है:
अंतिम तिथि यथा 31.05.2018 तक एअर इंडिया के नीतिगत विनिवेश के लिए कोई बोली प्राप्त न होने के पश्चात, एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) ने दिनांक 18.06.2018 को आयोजित अपनी बैठक में इस समय अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि:
i) एअर इंडिया की प्रचालनिक कुशलता को प्राप्त करने और कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सभी मध्यकालीन प्रयास किए जाएं,
ii) गैर-महत्वपूर्ण भूमि तथा भवन परिसंपत्तियों, जिन्हें पहले ही चिह्नित किया गया है, का मुद्रीकरण किया जाए।
iii) परिसंपत्तियों को एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड में शिफ्ट किया जाए ताकि एअर इंडिया के कर्ज को कम किया जा सके, और;
iv) उपर्युक्त गतिविधियों के निष्पादन के लिए मौजूदा सलाहकारों की सेवाओं का प्रयोग किया जाए।
सरकार ने एअर इंडिया लिमिटेड को निदेश दिए हैं कि वे एअर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचना के पश्चात अपने नए सदस्यों के साथ एआईएसएएम एअर इंडिया के विनिवेश हेतु मापदंडों को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

(ख): एअर इंडिया संघों/एसोसिएशनों/गिल्ड /फेडरेशन/ट्रस्ट के संयुक्त फॉरम ने एअर इंडिया को लिखे दिनांक 12.06.2019 के अपने पत्र के तहत एअर इंडिया के निजीकरण के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। तथापि, इस संबंध में एअर इंडिया के प्रबंधन द्वारा कोई आधिकारिक सूचना प्रदान नहीं की गई है।

(ग): पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के लिए एअर इंडिया के कुल ऋण और निवल घाटों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है (रूपए करोड़ में):

वर्ष.....निवल घाटा.....कुल ऋण
2018-19.....7635.00(अनन्तिम)....58351.93 (अनन्तिम)
2017-18..... 5348.18..... 55308.52
2016-17..... 6452.89.....48447.37
2015-16..... 3836.78..... 52817.02

(घ): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में सरकार द्वारा एअर इंडिया को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा निम्नांनुसार है (रूपए करोड़ में):
वर्ष.....राशि
2018-19..... 3975.00
2017-18..... 1800.00
2016-17..... 2465.21
2015-16..... 3300.00;

(ड.): सरकार ने एअर इंडिया के लिए जीर्णोद्धार योजना तैयार की है, जिसमें वृहत वित्तीय पैकेज शामिल है। एअर इंडिया के जीर्णोद्धार योजना में प्रचालनिक कुशलताओं पर बल दिया गया है ताकि राजस्व में व्यापक वृद्धि और लागत में बचत की स्थिति प्राप्त की जा सके। जीर्णोद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अनेक प्रमुख तत्व भी शामिल हैं यथा:
(i) प्रबंधन को सुदृढ बनाकर तथा सर्वोत्तम पद्धति व्यवसाय प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन द्वारा प्रचालनिक कुशलता के उच्चतम स्तर।
(ii) प्रबुद्ध बोर्ड द्वारा सुदृढ़ संगठनात्मक और शासन सुधार उपायों को क्रियान्वित किया जाएगा।
(iii) एअर इंडिया के सभी प्रमुख व्यवसायों के लिए भिन्न -भिन्न व्यवसाय रणनीतियों का उपयोग करना।
(iv) प्रतिभावान एवं प्रेरित कार्य बल के निर्माण के सुनिश्चिय के लिए विश्व स्तरीय मानव संसाधन व्यवहार अपनाना, तथा
(v) गैर-प्रमुख स्थावर सम्पतियों की बिक्री तथा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) जैसी सहायक कम्पनियों में रणनीतिक विनिवेश करना।
इसके अतिरिक्त, हालांकि सरकार एअर इंडिया के विनिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है, सरकान ने वित्तीय सहायता से एअर इंडिया के जीर्णोद्धार योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। वित्तीय सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ, एअर इंडिया को 3975 करोड़ रूपए की रोकड़ सहायता, 29464 करोड़ रूपए की राशि के कर्ज को एअर इंडिया लिमिटेड से विशेष कार्य योजना (एसपीवी) यथा एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को अंतरित करना, एअर इंडिया लिमिटेड को 7600 करोड़ रूपए की सरकारी गारंटी उपलब्ध कराना और एसपीवी को ऋण अंतरण के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी/चौथी तिमाही हेतु ब्याज को पूरा करने के लिए एसपीवी को 1300 करोड़ प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त एसपीवी ऋण पर सम्पूर्ण कर्ज को सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेवित किया जाएगा, जिसके लिए 2600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, एआईएसएएम अपनी पुनर्संरचना पर अपने नए सदस्यों के साथ एअर इंडिया के विनिवेश के मापदंडों को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

*****